

ResearchPro International Multidisciplinary Journal

Vol- 1, Issue- 2, October-December 2025

ISSN (O)- 3107-9679

Email id: editor@researchprojournal.com

Website- www.researchprojournal.com



भारत में AI संचालित गिग इकोनॉमी और रोजगार के बदलते स्वरूप: एक अध्ययन

शीलू कुमारी

शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, बी. एन. एम. यू., मधेपुरा।

सारांश: भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा संचालित एक नए युग के मुहाने पर खड़ा है, जहाँ प्रौद्योगिकी जीवन को बदल रही है और राष्ट्र की प्रगति को आकार दे रही है। एआई अब केवल अनुसंधान प्रयोगशालाओं या बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। यह हर स्तर पर नागरिकों तक पहुँच रहा है। दूर-दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवा की पहुँच में सुधार लाने से लेकर किसानों को पूरी जानकारी के साथ फसल संबंधी निर्णय लेने में मदद करने तक, एआई दैनिक जीवन को सरल, स्मार्ट और अधिक कनेक्टेड बना रहा है। यह व्यक्तिगत शिक्षा के माध्यम से कक्षाओं में क्रांति ला रहा है, शहरों को स्वच्छ और सुरक्षित बना रहा है, और तेज, डेटा संचालित शासन के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बना रहा है। इंडिया एआई मिशन और एआई उत्कृष्टता केंद्र जैसी पहलें इस परिवर्तन के केंद्र में हैं। ये पहलें कंप्यूटिंग पावर तक पहुँच का विस्तार कर रही हैं, अनुसंधान को समर्थन दे रही हैं, और स्टार्टअप्स तथा संस्थानों को ऐसे समाधान तैयार करने में मदद कर रही हैं जिनसे लोगों को सीधे तौर पर लाभ पहुँचे। भारत का दृष्टिकोण एआई को खुला, किफायती और सुलभ बनाने पर केंद्रित है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नवाचार समग्र रूप से समाज का उत्थान करे।

कुँजी: कृत्रिम, प्रौद्योगिकी, प्रयोगशाला, अनुसंधान, शिक्षा।

प्रस्तावना: भारत की गिग इकोनॉमी तीव्र गति से विस्तार कर रही है, जहाँ वर्तमान में 7.7 मिलियन से अधिक प्लेटफॉर्म वर्कर कार्यरत हैं और वर्ष 2030 तक इनके 23 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है। लेकिन जैसे-जैसे ग्रीष्म ऋतु और अधिक भीषण होती जा रही है, डििलीवरी राइडर, ड्राइवर और कूरियर जैसे इस जरूरी कार्यबल को एक ऐसे खतरे का सामना करना पड़ रहा जिसे नीतिगत स्तर पर व्यापक रूप से अनदेखा किया गया है: अत्यधिक तापमान (extreme heat)। वेतनभोगी कर्मचारियों के विपरीत, गिग वर्कर बिना आय – हानि के कार्य से विराम नहीं ले सकते, जिससे उन्हें प्रतिदिन स्वास्थ्य और आय के बीच एक जोखिमपूर्ण संतुलन स्थापित करना पड़ता है। भारत की हीट एक्शन योजनाएँ (Heat Action Plans) मुख्यतः मृत्यु-दर को कम करने पर केंद्रित हैं, लेकिन लू के कारण इन वर्कर्स को होने वाले अप्रत्यक्ष मूक आय- आघातों (silent income shocks) को संबोधित नहीं करतीं। इसलिये भीषण गर्मी कोई अलग संकट नहीं है, बल्कि यह उस कार्यबल के लिये एक कठिन परीक्षा है जो पहले से ही नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा या बुनियादी सुरक्षा जाल के बिना काम कर रहा है।

इस शोध का उद्देश्य गिग इकोनॉमी और आर्थिक विकास के बीच गतिशील संबंध का पता लगाना है, जिसमें सुविधा के इस बदलते युग में रोजगार के अवसरों, कार्य-संबंधी चुनौतियों और नीतिगत प्रभावों पर विशेष ध्यान दिया गया है। गिग इकोनॉमी फ्रीलांसिंग और अनुबंध के अवसरों के माध्यम से काम की परिभाषा को बदल रही है। गिग इकोनॉमी का विकास हो रहा है और अनुमान है कि 2032 तक इसका बाजार आकार 1847 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा। इस अध्ययन में गिग श्रमिकों से डेटा एकत्र करने के लिए गैर-संभाव्यता गुणात्मक अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया गया। इस अध्ययन में भारत के दिल्ली में 23 गिग श्रमिकों के साथ अर्ध-संरचित साक्षात्कार आयोजित किए गए और विषयगत कोडिंग के लिए छटपट 12.0 का उपयोग किया गया, जिससे

उनके कार्य अनुभव को प्रभावित करने वाले सात प्रमुख आयामों की पहचान की गई। अध्ययन के परिणामों से सात प्रमुख आयाम सामने आए रू आर्थिक स्थिरता, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की नीतियां, सरकारी नीतियां, नौकरी की सुरक्षा, कार्य लचीलापन, गिग इकॉनमी का प्रभाव और असंगत कार्य विकल्प। अध्ययन के निष्कर्ष श्रम अर्थशास्त्र, डिजिटल रोजगार प्लेटफॉर्म और वैकल्पिक रोजगार संरचनाओं के मौजूदा साहित्य को समृद्ध करते हैं। यह अध्ययन नीति निर्माताओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रबंधकों के लिए रणनीतिक सिफारिशें प्रस्तुत करता है और गिग इकॉनमी पहलू में भविष्य के अकादमिक अनुसंधान के लिए एक आधार प्रदान करता है।

साक्षात्कार डिजाइन

जांच करने के लिए जीवित अनुभव गिग का श्रमिकों, अध्ययन एक का इस्तेमाल किया। अर्ध-संरचित साक्षात्कार प्रारूप जिसने अनुमति दी प्रतिभागियों को खुले तौर पर उनका खुलासा करें। दृष्टिकोण, समस्याएं और सामना करने की तकनीकें एक साक्षात्कार की रूप-रेखा इसका निर्माण इस आधार पर किया गया था। प्रमुख विषय पर क्षेत्रों को गारंटी स्थिरता बनाए रखते हुए बातचीत की स्वतंत्रता। इन विषय शामिल नौकरी इतिहास और प्रेरणा, काम प्रकार और शेड्यूलिंग, प्लेटफॉर्म सगाई और नियंत्रण, आय पैटर्न और वित्तीय स्थिरता, लाभ और सुरक्षा, लक्ष्य और भविष्य देखना। इन खुले प्रश्नों ने अनुमति दी विस्तृत उत्तरों के लिए, प्रचारित अनुवर्ती पूछताछ की और दिया आवश्यक प्रासंगिक लचीलापन जटिल अनुभवों को समझने के लिए।

डेटा विश्लेषण

गुणात्मक सॉफ्टवेयर एनवीवो 12.0 का उपयोग किया गया था कोड करने के लिए और विश्लेषण करें साक्षात्कार प्रतिलेख के रूप में का हिस्सा आंकड़ा प्रसंस्करण प्रक्रिया। विषयगत विश्लेषण था इस्तेमाल किया गया को उजागर प्रमुख पैटर्न और अंतर्दृष्टि वह उभरा से जीम डेटा प्रक्रिया शामिल का अनेक चरण: शुरू में, जीम शोधकर्ताओं परिचित खुद साथ टेप के माध्यम से दोहराया गया पढ़ता है। प्रथम वर्गीकरण था तब द्वारा पूर्ण की गयी। लेबलिंग कुंजी कथन और अवलोकन। इन कोड थे अंततः संयुक्त अंतर्गत बड़े विषय शामिल आय, स्थिरता, काम लचीलापन, नियामक मुद्दे, और डिजिटल प्लेटफॉर्म निर्भरता। अंततः विषय वस्तु का मूल्यांकन किया गया और संशोधित किया गया बनाना जरूर संगति और वैधता। तालिका नंबर एक शो जनसांख्यिकी और औद्योगिक विशेषताएं गिग वर्कर्स जिसके लिए साक्षात्कार लिया गया अध्ययन।

रोजगार के बदलते स्वरूप पर AI का प्रभाव (Impact of AI) :

- **एल्गोरिथम प्रबंधन:** AI और मशीन लर्निंग (ML) अब ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी और अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्मों पर जॉब एलोकेशन (काम का आवंटन), डायनेमिक प्राइसिंग (किराया निर्धारण), और प्रदर्शन ट्रैकिंग को नियंत्रित कर रहे हैं।

- **हाइब्रिड वर्क (Algorithm & Human Manager):** श्रमिक अब पूरी तरह से मानवीय पर्यवेक्षण के बजाय AI-संचालित एल्गोरिथम के तहत काम कर रहे हैं, जिसे अक्सर 'एल्गोरिथमिक-ह्यूमन मैनेजर' कहा जा रहा है।

- **कौशल की मांग:** 'डिग्री-फर्स्ट' से 'स्किल-फर्स्ट' (कौशल- प्रथम) नियुक्तियों की ओर बदलाव हुआ है, जहाँ 40% से अधिक IT और गिग कार्यबल उत्पादकता के लिए AI उपकरणों का उपयोग कर रहा है।

समावेशी सामाजिक विकास के लिए एआई

नीति आयोग की रिपोर्ट, 'समावेशी सामाजिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (अक्टूबर 2025), भारत के अनौपचारिक कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का एक रोडमैप प्रस्तुत करती है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछती है: दुनिया की सबसे उन्नत प्रौद्योगिकियां सबसे अधिक उपेक्षित श्रमिकों तक कैसे पहुँच सकती हैं, जिससे वे अपनी बाधाओं को पार कर सकें और भारत की विकास गाथा में अपना स्थान बना सकें?

यह रिपोर्ट अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित है। यह राजकोट के एक घरेलू स्वास्थ्य सेवा सहायक, दिल्ली के एक बढ़ई, एक किसान और कई अन्य लोगों की चुनौतियों और आकांक्षाओं को दर्शाती है। ये कहानियाँ लगातार आने वाली बाधाओं को दर्शाती हैं, लेकिन साथ ही उन अपार संभावनाओं को भी दर्शाती हैं जिन्हें सोच- समझकर इस्तेमाल की गई प्रौद्योगिकी उजागर कर सकती है। इन लाखों लोगों के लिए, प्रौद्योगिकी को उनके कौशल का स्थान लेने के बजाय, उसे और बढ़ाना चाहिए। रोडमैप में चर्चा की गई है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स और इमर्सिव लर्निंग भारत के 49 करोड़ अनौपचारिक कामगारों के सामने आने वाली व्यवस्थागत बाधाओं को कर सकते हैं। यह एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहाँ साल 2035 तक, वॉयस- फर्स्ट एआई इंटरफेस भाषा और साक्षरता की बाधाओं को दूर कर देंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समय पर और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

माइक्रो-क्रेडेंशियल और ऑन डिमांड लर्निंग, कामगारों को उनकी महत्वाकांक्षा के अनुसार कौशल बढ़ाने में मदद करेंगे।

इस विजन का मूल डिजिटल श्रमसेतु मिशन है, जो भारत के अनौपचारिक क्षेत्र के लिए अग्रणी तकनीकों को बड़े पैमाने पर लागू करने की एक राष्ट्रीय पहल है। यह मिशन व्यक्ति – आधारित या क्षेत्र आधारित प्राथमिकता, राज्य – संचालित कार्यान्वयन, नियामक सक्षमता और रणनीतिक साझेदारियों पर केंद्रित है, जिससे सामर्थ्य और व्यापक स्वीकृति सुनिश्चित की जा सके। यह एक मजबूत बहु-स्तरीय प्रभाव मूल्यांकन ढाँचे द्वारा निर्देशित होकर सरकार, उद्योग और नागरिक समाज को संगठित करेगा।

रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि इस समावेशी डिजिटल उछाल को हासिल करने के लिए सिर्फ आशावाद से कहीं ज्यादा की जरूरत होगी। इसमें अनुसंधान एवं विकास, लक्षित कौशल कार्यक्रमों और एक मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में टोस निवेश की जरूरत बताई गई है। आधार, यूपीआई और जनधन जैसी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाओं के क्षेत्र में भारत की पिछली सफलताएँ दर्शाती हैं कि समावेशी, व्यापक मंच संभव हैं।

गिग इकॉनमी ई-कॉमर्स, परिवहन और डिलीवरी सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती है और उम्मीद है कि यह 2030 तक 90 मिलियन नौकरियां सृजित करेगी और भारत की जीडीपी में 1.25: का योगदान देगी।

नीति आयोग के अनुसार, भारत में गिग वर्क की मांग लगातार बढ़ रही है। 2011 से 2020 तक की अवधि में गिग वर्कर्स के लिए जीडीपी वृद्धि दर के सापेक्ष रोजगार लोच एक से अधिक रही और यह समग्र रोजगार लोच से भी अधिक थी। गिग वर्कर्स के लिए उच्च रोजगार लोच से आर्थिक विकास की प्रकृति का स्पष्ट संकेत मिलता है, जिसके कारण गैर-गिग वर्कर्स की तुलना में गिग वर्कर्स की मांग अधिक हुई है। अर्थव्यवस्था में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि गैर- गिग वर्क का गिग वर्क में अधिक रूपांतरण हो रहा है।

हालांकि यह सच है, फिर भी गिग वर्कर्स को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि उनके साथ दुर्व्यवहार और भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में गिग वर्कर्स के लिए कानूनी ढांचा ठीक से तैयार न होना या अभी तक तैयार न होना। इससे ऐसे नियम और कानून बनते हैं जो गिग वर्कर्स के सामने आने वाले खतरों और चुनौतियों का समाधान करने में अप्रभावी हैं। आय में उतार-चढ़ाव के कारण गिग वर्कर्स को अस्थिरता और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, जिससे आर्थिक मंदी के दौरान उनकी असुरक्षा बढ़ जाती है। गिग वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति योजना आदि जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का अभाव सार्वजनिक कल्याण प्रणालियों पर दबाव डाल सकता है और आय वितरण में असमानता बढ़ा सकता है। गिग वर्कर्स को नियंत्रित करने वाले अपर्याप्त कानून और श्रमिक सुरक्षा और कार्य वातावरण की कमी बड़े पैमाने पर शोषण का कारण बन सकती है।

निष्कर्ष: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत की यात्रा एक स्पष्ट दृष्टि और निर्णायक कार्रवाई को दर्शाती है। कंप्यूटिंग अवसंरचना के विस्तार से लेकर घरेलू मॉडलों को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स को समर्थन देने तक देश एक मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है जो नागरिकों को लाभान्वित करता है और नवाचार को बढ़ावा देता है। कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन के क्षेत्र में की गई पहलों के व्यावहारिक अनुप्रयोग वास्तविक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इंडिया एआई मिशन, डिजिटल श्रमसेतु और आधारभूत मॉडल विकास जैसी रणनीतिक पहलें यह सुनिश्चित कर रही हैं कि नवाचार प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे और साथ ही अनुसंधान, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिले। ये प्रयास भारत को एक वैश्विक एआई नेता के रूप में उभरने और विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

सन्दर्भ ग्रंथ सूची-

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2132817>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2108810>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113095>
- <https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149242>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2132377>
- <https://indiaai.gov.in/article/building-india-s-foundational-ai-models-indiaai-innovation-initiative>
- <https://indiaai.gov.in/globalindiaaisummit/about-global-indiaai-summit>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2108961>
- <https://aikosh.indiaai.gov.in/home>
- <https://bhashini.gov.in/about-bhashini>
- <https://bhashini.gov.in>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2135178>

Cite this Article

"शीलू कुमारी", "भारत में AI संचालित गिग इकोनॉमी और रोजगार के बदलते स्वरूप: एक अध्ययन", ResearchPro International Multidisciplinary Journal (RPIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:1, Issue:2, October-December 2025.

Journal URL- <https://www.researchprojournal.com/>

DOI- 10.70650/rpimj.2025v1i2000019